U.N. Survey on slaves in India

578. SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the fact that according to a U.N. Survey, India has the distinction of having 5 million slaves; and

(b) if so, what is Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) The U.N. have not conducted any such survey.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

579. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और उनमें से कितने मामलों में प्रतिष्ठानों को दोषी पाया गया तथा उनमें से प्रत्येक के विरूद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन निरीक्षण श्रम प्रवर्तन अधि- (केन्द्रीय) द्वारा किए जाते हैं । वर्ष 1979 (केन्द्रीय) द्वारा किए जाते हैं । वर्ष 1979 से 1981 के दौरान प्रवर्तन प्राधिकारियों अर्थात सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय) और सहायक श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) ने बिहार में 8,888 निरीक्षण किए जिनके परिणामस्वरूप 45,698 अनियमितताओं का पता लगाया गया और 1225 अभियोजन दायर किए गये । क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद ने भी ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अधीन अगस्त 1981 में दो प्रतिष्ठानों के बारे में स्वयं जांच निरीक्षण किए ताकि उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले किये गये निरीक्षणों का जांच निरीक्षण किया जा सके ।

गंगा पुल के कर्मकारों को मुआवजे का भुगतान

580. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेमन इन्डिया लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन गंगा पुल में किस ग्रेड के कितने लोग काम पर लगाये गए थे और अभी कितने लोग वहां काम पर हैं;

(ख) कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए कितने और घायल काम के लायक नहीं रहे;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या उक्त कम्पनी द्वारा श्रम कानून लागू किये गए हैं; यदि हां, तो मजदूरों का कितना बकाया किस मद में कम्पनी के जिम्मे भुगतान हेतु कब से लम्बित है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मोहसिना किदवई): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

Labourers engaged by Central and State Governments for construction work

581. SHRI G. C. BHATTACHARYA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Hindustan Times dated the 21st August, 1982 to the effect that the Rajasthani Bhil labourers as also other construction labourers engaged in construction work of Central Government and the Central Government and the State Governments are living under abject conditions; and

(b) whether Government will provide minimum and bare amenities and shelter to these labourers and set example as an ideal employer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) On the news item relating to Rajasthani Bhil labourers referred to, Delhi Development Authority have reported that a number of bhil families are living in an area known as Bhil Basti in Baljit Nagar near West Patel Nagar which is a notified slum and that basic amenities like drinking water, electricity and footpaths in the colony have been provided.

(b) The Delhi Development Authority have further reported that their Slum Department is proposing to carry out a socio-economic survey of Baljit Nagar to ascertain the extent of the problems and their appropriate solution by providing some of the basic amenities of life and by improving the environments subject to availability of funds during the next financial year.

Textile workers strike in Bombay

582. SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether trade union leaders have held any talks with the Central Government to settle textile workers strike in Bombay;

(b) whether it is a fact that the strike was called by a non-recognised union; and

(c) if so, what action Government propose to take to stop the non-recognised union giving call for the strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The strike has been called by an un-recognised union.

(c) An illegal strike, an unfair labour practice under the Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 is an offence punishable under the Act.

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के निर्देश

583. **श्री राम भगत पासवान** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, संबंधित सरकार अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए सक्षम है । जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने सिफारिश की कि संबंधित सरकारों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे समय-समय पर अनुसूची में यथा- संभव अधिक रोजगारों को शामिल करके कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि न्यूनतम मजदूरी दरों को, यदि आवश्यक हो, कम से कम, दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 पाइंटों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उनमें संवर्धन किया जाना चाहिए । इस सिफारिश को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया ।

Payment to National Herald Employees

584. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Provident Fund and E.S.I. re-imbursement have not been paid to the employees of National Herald and yet they are starting new editions of the paper from other State capitals; and